

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर ।

**:: निर्णय ::**

ओम प्रकाश

बनाम्

राजस्थान राज्य ।

एकलपीठ दण्डिक जेल अपील संख्या- 260/2006  
अन्तर्गत धारा- 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, बविरूद्ध  
श्री अजय कुमार मीणा, आर.एच.जे.एस., अपर जिला एवं  
सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), जयपुर जिला- जयपुर द्वारा  
सेशन प्रकरण संख्या- 39/2002 (84/2001) में पारित  
निर्णय दिनांक- 7 नवम्बर, 2003

-----

**निर्णय दिनांक-**

**जनवरी 04, 2007**

**माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा**

श्री अंशुमान सक्सेना, अधिवक्ता]

श्री अमित पूनिया, अधिवक्ता ]वास्ते अपीलार्थी।

श्री एम.एल. गोयल, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

-----

**न्यायालय द्वारा-**

(1) अपीलार्थी ने इस दण्डिक अपील में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), जयपुर जिला- जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक- 7.11.2003 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 100/-रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं अदम अदायगी अर्थदण्ड 15 दिन के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने के निर्देश दिए गये हैं।

(2) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादिया सुशीला ने पुलिस थाना कालवाड़ जिला- जयपुर पर अपनी छोटी बहिन रानी के साथ उपस्थित होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श- P-1) इस आशय की प्रस्तुत की कि उसके सगे पिता उसके

साथ जबरदस्ती संभोग करते हैं। उसने कई बार रोकने की कोशिश की, परन्तु रात को शराब पीकर उसके साथ गन्दा काम करते हैं। उसकी बड़ी बहन के साथ भी गन्दा काम करते थे, जिसने दुखी होकर आत्म हत्या करली। उक्त तहरीरी रिपोर्ट में परिवादिया ने उसके साथ किए गये संभोग का विवेचन भी किया है। पुलिस थाना, कालवाड़, जयपुर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 376 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया और प्रकरण में अन्वीक्षा प्रारम्भ की गई। परिवादिया सुशीला का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया तथा अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। परिवादिया सुशीला के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-164 के अन्तर्गत लेखबद्ध करवाये गये। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो जाने के उपरान्त प्रकरण में चालना प्रस्तुत किया गया। तदुपरान्त प्रकरण विचारण हेतु अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक), जयपुर जिला- जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 376 एवं 306 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गये। अपीलार्थी द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में 9 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया तथा 14 प्रलेख प्रदर्शित करवाया गये। अपीलार्थी के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अन्तर्गत लेखबद्ध किए गये जिसमें अपीलार्थी ने स्वयं को निर्दोष बताया तथा कथन किया कि वह सुबह 6.00 बजे दुकान खोलता है तथा 8.00 बजे बंद करता था। उसके पड़ोसी रामकुमार सिंह के लड़के शराब का धन्धा करते हैं जो उसकी गैर मौजूदगी में बच्चियों के पास आते-जाते थे, जो उसे बर्दाश्त नहीं था। उसे पता लगने पर उसने सुशील, रूमी को समझाया, लड़को को धमकाया तथा रामकुमारसिंह को उलाहना दिया और सुशीला के थप्पड़ मारे और घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी, इस कारण बच्ची नाराज थी और उसके खिलाफ रिपोर्ट करा दी। अपीलार्थी की ओर से प्रतिरक्षा में ओमप्रकाश, बनवारी लाल, नंदलाल एवं मदन शर्मा को परीक्षित करवाया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की साक्ष्य को विस्तार पूर्वक विवेचित करते हुए अपीलार्थी को उपरोक्त प्रकार से दोषसिद्ध व दण्डित किया।

- (3) अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमान सक्सेना ने मेरे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी के जेल जाने के उपरान्त परिवादिया सुशीला व रानी को बाल आश्रम, गाँधी नगर, जयपुर में रखा गया था। बाल आश्रम से परिवादिया सुशीला का विवाह हो चुका है एवं बाल आश्रम से रानी ने अपीलार्थी को कई पत्र लिखे हैं, जिनमें अभिकथित किया है कि उसने लोगों के

बहकावे में आकर अपीलार्थी के विरुद्ध झूठे बयान दिए हैं। उन्होंने रानी द्वारा अपीलार्थी को लिखे गये छः मूल पत्र भी अनुशीलनार्थ मेरे समक्ष प्रस्तुत किए, जिनमें से दिनांक- 12-5-2005 का एक पत्र सुशीला व रानी द्वारा अपीलार्थी को लिखा गया है, जो अपीलार्थी को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर भेजा गया था, जिसमें सुशीला व रानी ने निम्न तथ्य अंकित किए हैं:-

"आदरणीय पिताजी,

को सुशीला रूमी की ढोक। आगे समाचार आपकी चिट्ठी हमें कल मिली पढ़कर बहुत खुशी हुई और यह भी पता चला कि हमारी दोनों चिट्ठी आपको मिल गई। सुशीला दीदी तो पत्र पढ़कर रोये ही जा रही हैं। हमारे लिये आज का दिन बेहद खुशी का दिन है। आपने दीदी को व मुझे माफ कर दिया है। हमें तो पापा ऐसा लग रहा था कि इस पाप के लिए आप हमें कभी माफ नहीं करेंगे। पिताजी आप महान हैं। एक देवता हैं। आपने हमें माफ कर दिया। हम दोनों बहुत ही शर्मीन्दा हैं कि लोगों के बहकावे व लालच में आकर हमसे बहुत बुरा हो गया। पापा उस समय हम इतनी समझती ही नहीं थी कि इसका क्या असर होगा हम तो पापा एक ही जानते थे कि किसी भी तरह आपको खोना नहीं चाहते थे। मम्मी के लिए भी आपने पानी की तरह पैसे बहाये ज्यान लड़ा दी थी आपने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी नहीं बची। उसके बाद हमारे लिए आप ने क्या क्या नहीं किया। कभी हमें मम्मी पापा की कमी नहीं आने दी। इसलिए पापा अगर आप नहीं रहे तो किसके सहारे कहाँ रहेगी इसलिए आपको ठीक कराने के लिए हम इनके बहकावे में आकर झूठ बोली थी अब पापा सब इनकी झूठ सामने आ गयी। अपने को बर्बाद कर दिया इन्होंने देखना पापा इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इनके अन्दर भी ऐसा ही होगा और पापा आप जैसे भी हो आप केस लड़े और हो सके तो हमें भी एक बार अदालत में सच बोलने का मौका दिला दे तो पापा सुशीला दीदी व मैं अदालत को सारी बात बतायेंगी की कैसे उन लोगों ने हमारे साथ झूठ बोलकर धोखा किया और हमें हमारे पापा से अलग किया....."

(4) उक्त पत्र के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मेरे समक्ष तर्क प्रस्तुत किया है कि जो प्रकरण अपीलार्थी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है वह मिथ्या है, अतः अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

(5) विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी एवं सुयोग्य लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को ध्यान पूर्वक सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(6) सुशीला (अभि. साक्षी सं.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में निम्न कथन किया है:-

"मेरे पिता मुल्जिम ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की , मेरे कपड़े खोल दिये थे और अपना लिंग मेरी योनी में डालने की कोशिश की, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटा हूं, मैंने उसके बाद धक्का दिया और मैं कपड़े लेकर कमरे से बाहर भाग गई और मैं बाहर बैठी रही। इस प्रकार 2-3 बार प्रयास किया। .....पापा ने मेरे 2-3 थप्पड़ की मारी और फिर रात को जबरदस्ती गलत काम करने लगे और अपना लिंग मेरी योनी में डाल दिया। मुझे पापा मारते थे इसलिए मैं चिल्लाई नहीं।..... यह घटना मई-जून की है, उसके बाद भी 2-4 बार मेरे साथ इसी प्रकार गलत काम किया और कुल मिलाकर करीब एक वर्ष तक खोटा काम करते रहे..... मैं 15 साल की थी तब से मुल्जिम मेरे साथ गलत काम कर रहा है। मेरे कपड़े भी मुल्जिम जबरदस्ती खोलता था....."

(7) विचारण न्यायालय के समक्ष जो प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत हुई है जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श- P/11) में परिवादिया सुशील की सलवार व कच्चे पर ब्रूमन सीमन पाया गया है और मैं संतुष्ट हूं कि विचारण न्यायालय ने जो अपीलार्थी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 के अन्तर्गत दोषसिद्धि की है उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। जहाँ तक विचारण न्यायालय के निर्णय के उपरान्त परिवादिया सुशीला व रानी द्वारा अपीलार्थी को लिखे गये पत्रों का सम्बन्ध है, उनसे यह प्रकट होता है कि दोनों बच्चियों ने अपीलार्थी के विरुद्ध दी गई साक्ष्य के सम्बन्ध में प्रायश्चित्त करने का प्रयास किया है, किन्तु सर्वमान्य विधिक स्थिति अनुसार आक्षेपित निर्णय के उपरान्त लिखे गये उक्त पत्रों को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता और न ही उक्त पत्रों के आधार पर उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दी गई साक्ष्य को झुटलाया जा सकता है, किन्तु न्याय के हित में व प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में दण्डाज्ञा की शिथिलता के सम्बन्ध में अवश्य ही उक्त पत्रों को प्रलेखित किया जा सकता है।

(8) भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 376 के अन्तर्गत यह निर्दिष्ट है कि उक्त अपराध के लिए सात वर्ष से कम की सजा नहीं दी जा सकती, किन्तु उक्त धारा के साथ जो परन्तुक जोड़ा गया है उसके अनुसार यथोचित और विशेष कारण

(Adequate and special reasons) बताने पर सजा सात वर्ष से कम भी की जा सकती है। जो पत्र प्रस्तुत किए गये हैं वे किसी भी प्रकार से परिवादिया सुशीला द्वारा न्यायालय में दी गई साक्ष्य को कानून की दृष्टि में खण्डित नहीं करते हैं एवं उक्त पत्रों के आधार पर सुशीला की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता, किन्तु इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अपीलार्थी 17.7.2001 से निरन्तर अभिरक्षा में चला आ रहा है एवं परिवादिया सुशीला के कथन विचारण न्यायालय के समक्ष 21.12.2002 को लेखबद्ध किए गये थे, उस समय उसकी आयु 16 वर्ष थी और इसी तरह से जो रानी के कथन लेखबद्ध किए गये थे उन्हें शपथ के आधार पर दिए गये कथन नहीं माना जा सकता। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में यदि अपीलार्थी को 7 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है तो इससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

(9) अतः यह अपील निम्न प्रकार निस्तारित की जाती है:-

(A) विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 के अन्तर्गत की गई दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

(B) विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित आक्षेपित दण्डाज्ञा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 15 दिन अतिरिक्त कठोर कारावास को संशोधित करते हुए अपीलार्थी को 7 वर्ष कठोर कारावास एवं 100/-रूपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड 15 के अतिरिक्त कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

(C) विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय उपरोक्त प्रकार से संशोधित किया जाता है।

**(न्या. शिव कुमार शर्मा)**